एलआईसी क्लास 1 अधिकारी एसिओसेशनो का फेडरेशन,
नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया,
अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी एसिओसेशन
अखिल भारतीय एलआईसी कर्मचारी फेडरेशन

प्रति
सभी एलआईसी कर्मचारी

Date: 14.01.2022,

प्रिय साथियों/मित्रों,

विषय: 19 जनवरी 2022 का प्रेक्षण - जीवन बीमा दिवस का राष्ट्रीयकरण- जैसे "सार्वजनिक क्षेत्र को बचाएं, एलआईसी दिवस को मजबूत करें"

19 जनवरी एलआईसी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ऐतिहासिक महत्व का दिन है। साढ़े छह दशक पहले 19 जनवरी 1956 को जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण की दिशा में पहला कदम उठाया गया था। तत्कालीन भारत सरकार ने जीवन बीमा (आपातकालीन प्रावधान) अध्यादेश 1956 को प्रख्यापित किया और 154 भारतीय बीमा कंपनियों, 16 विदेशी बीमा कंपनियों और 75 भविष्य निधि समितियों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। 20 जनवरी 1956 तक, भारत सरकार द्वारा नियुक्त 42 अभिरक्षकों द्वारा सभी जीवन बीमा कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया गया था। 19 जनवरी 1956 और 31 अगस्त 1956 के बीच की अवधि का उपयोग विभिन्न बीमा कंपनियों के एकल राज्य के स्वामित्व वाले निगम में एकीकरण की सुविधा के लिए तैयारी की अवधि के रूप में किया गया था। इसलिए 19 जनवरी पूरे भारत में एलआईसी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए न केवल बहुत प्रिय है, बल्कि यह आश्वासन का दिन है, हमारे दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता को मजबूत करने का दिन है और एलआईसी की सार्वजनिक क्षेत्र में सुरक्षा के लिए नए जोश के साथ आगे बढ़ने का दिन है।

बीमा के राष्ट्रीयकरण का विचार वास्तव में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय चेतना का एक अभिन्न अंग था। 1931 में कांग्रेस के कराँची अधिवेशन ने यह कहते हुए स्वर तय किया था कि राजनीतिक स्वतंत्रता में लाखों भूखे लोगों के लिए वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता

शामिल होनी चाहिए। भारतीय संविधान की रचना करने वाली संविधान सभा ने 1948 में एक प्रस्ताव पारित किया और संकल्प लिया कि राज्य को बीमा के व्यवसाय का प्रबंधन करना चाहिए। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अम्बेडकर स्वयं इस बात के इच्छुक थे कि "बीमा का राष्ट्रीयकरण और प्रबंधन राज्य द्वारा किया जाना चाहिए"।

इसके कुछ निकटवर्ती कारण भी थे कि क्यों जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण जल्दबाजी में, गुप्त रूप से, सार्वजनिक चकाचौंध से दूर किया जाना था। निजी बीमा कम्पनियों के स्वामियों की लूट-खसोट इस कदर पहुँच चुकी थी कि भारत के तत्कालीन शासकों को जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण के निर्णय को गुप्त रखना पड़ा था। सरकार ने महसूस किया कि अध्यादेश जारी होने के थोड़े से संकेत पर निजी कंपनियों के मालिक अंतिम क्षणों में धांधली का सहारा ले सकते हैं। यह जानना दिलचस्प है कि 1945-55 के दशक में जितने 25 बीमाकर्ता परिसमापन में चले गए और उतनी ही संख्या को अपना व्यवसाय अन्य कंपनियों को स्थानांतरित करना पड़ा। जो कंपनियां बचने में कामयाब रहीं, 75 उनके पिछले 1953-54 के मूल्यांकन के आधार पर कोई बोनस घोषित करने में असमर्थ थे। यह कैसी त्रासदी है कि जब कंपनियाँ भारी घाटा उठा रही थीं, तब उनके मालिक बदबूदार विलासिता में लिप्त थे।

ऐसे मुश्किल समय में ही 1 सितंबर 1956 को LIC बहुत सारी उम्मीदों और आशाओं के साथ अस्तित्व में आई थी। राष्ट्र के नाम अपने प्रसारण में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. सी.डी. देशमुख ने विश्वास व्यक्त किया और कहा: "हम एक गतिशील और जोरदार संगठन को एक साथ जोड़ देंगे, जो पूरे देश में लोगों के हर क्षेत्र में बीमा लेने में सक्षम है और कुशल सेवा के साथ-साथ उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान करते हुए उनकी बचत को जुटाने में सक्षम है।"

उस वादे को पूरा करते हुए, एलआईसी ने पिछले कुछ वर्षों में न केवल जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है, बल्कि राष्ट्र निर्माण गतिविधियों के लिए समुदाय की बचत को चैनेलाइज करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 1956 में अपनी स्थापना के बाद से, LIC ने लाखों भारतीयों का विश्वास और सद्भावना अर्जित की है और कई मील पत्थर पार किए हैं। एलआईसी ने जीवन बीमा व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं में अभूतपूर्व प्रदर्शन रिकॉर्ड स्थापित किया है। रुपये की मामूली 5 करोड़ रुपये राशि के साथ अपना संचालन वर्ष 1956 में शुरू कर, एलआईसी आज 38 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खगोलीय रूप से विशाल संपत्ति के आधार पर है। यह 40 करोड़ से अधिक के ग्राहक आधार वाली पॉलिसियों की संख्या के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। इसकी 30 करोड़

व्यक्तिगत पोल्सियाँ लागू हैं और अन्य 12 करोड़ इसकी समूह पल;पोल्सियों के अंतर्गत आती हैं। जीवन बीमा कारोबार में दो दशकों से अधिक की प्रतिस्पर्धा के बाद भी, एलआईसी उद्योग में उच्चतम बाजार हिस्सेदारी के साथ खड़ा है। एलआईसी आज लाखों भारतीयों की पसंद का बीमाकर्ता है। दुर्भाग्य से, सार्वजनिक क्षेत्र की इस बेहतरीन संस्था को आज आईपीओ और शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग के नाम पर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आईपीओ के कदम का भारी जनमत के विरोध के बावजूद सरकार पूरी ताकत से आगे बढ़ रही है। पोल्सियों की ऑनलाइन बिक्री जैसे नए व्यापार चैनलों ने हमारे विशाल एजेंसी बल के लिए नई चुनौतियां पेश की हैं। एलआईसी के अलावा, 'आत्मनिर्भर भारत' की आड़ में बड़ी संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को विनिवेश और निजीकरण के लिए तैयार किया जा रहा है।

इसी संदर्भ में 30 दिसंबर 2021 को हुई संयुक्त मोर्चे की बैठक में 19 जनवरी 2022 को "सार्वजनिक क्षेत्र को बचाओ, एलआईसी को मजबूत करो दिवस" के रूप में मनाने का आह्वान करने का निर्णय लिया गया। हम पूरे देश में अपनी इकाइयों से इस अवसर को मनाने के लिए समन्वित तरीके से उपयुक्त कार्यक्रम आयोजित करने और सार्वजनिक क्षेत्र में एलआईसी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का आह्वान करते हैं।

अभिवादन के साथ,

आपके साथी

S. Rajkumar	**Vivek Singh**	**Shreekant Mishra**	**Rajesh Kumar**
General Secretary	Secretary General	General Secretary	General Secretary
Federation of LIC Class I Officers' Associations	NFIFWI	AIIEA	AILICEF